हमें एक ऐसी वैकल्पिक राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था स्थापित करनी है जो छः लाख गांवों में स्थानीय जल, जंगल एवं जमीन पर स्थानीय नियंत्रण की स्थापना के साथ-साथ खेती की भूमि पर खेती करने वाले किसान की मालकियत स्वीकार करती हो। गांव का हर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं सम्पन्न हो। इसके लिये ग्रामीण उद्योगों का ढांचा और उसका बुनियादी आधार इस प्रकार विकास के साथ जोड़ा जाये ताकि अन्तिम व्यक्ति भी गांव में अपना स्वतंत्र कारोबार चलाने में सक्षम हो। हर व्यक्ति स्वावलम्बी हो। आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये, जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि प्रत्येक व्यक्ति को बैंको या ए0टी0एम0 के द्वारा मुहैया कराई जाये ताकि हर व्यक्ति गौरव एवं स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके। यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि रू. 2000/- प्रति व्यक्ति प्रति माह तक मिलना चाहिये। इसका आधार राष्ट्रीय नैट-प्रॉफिट होगा।

राष्ट्रीय नैट प्रॉफिट (Nett Profit) का अभी तक आधार बड़ी औद्योगिक इकाईयां और बड़े औद्योगिक घराने माने जाते रहे हैं। परन्तु नई आर्थिक वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत इसका विस्तार करना होगा ताकि गांव से लेकर राष्ट्र के स्तर तक हर व्यक्ति को, अन्तिम व्यक्ति तक रू. 2000/- प्रति व्यक्ति प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि मुहैया कराई जा सके। इस प्रकार का आर्थिक आधार, गांव के स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की उद्योग में भागीदारी एवं स्वावलम्बन के आधार पर विकसित किया जाना चाहिये।

एक बात खासतौर पर याद रखने की है कि हिन्दुस्तान में कुल 600 शहर हैं और 6 लाख गांव। वर्तमान में 600 शहर 6 लाख गांवों को आर्थिक आधार पर पाल-पोस रहे हैं परन्तु स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद भी वे अविकसित भूखे-नंगे, बदरंग-बेहाल हैं, जहां हजारों किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं और लाखों गांव वाले न्याय की आस में कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं।

यदि ग्रामीण उद्योगों का ढांचा मजबूत कर दिया जाय, आधार कृषि-बागवानी-फल उत्पादन, जड़ी-बूटी आयुर्वेदिक कर दिया जाये, लुहार-बढ़ई-तेली- जुलाहे-चमड़ा आदि उद्योगों का आधार विकसित कर दिया जाये और सड़क, परिवहन, संचार-साधन, नलकूप, तालाब, सिंचाई, शिक्षा का ग्रामीण आधार आर्थिक बैंकिग के साथ जोड़ दिया जाये, तो यही 6 लाख गांव 600 शहरों की पाल-पोस करने के बाद भी स्वावलम्बी, समृद्ध और सम्पन्नता के प्रतीक बनकर एक वैभवशाली भारत का नवनिर्माण कर, स्वयं विकसित होकर स्वावलम्बी विकास की सक्षमता रखते हैं।

जिस देश में 40 लाख वेश्यावृत्ति करने, 2 करोड़ भीख मांगने, 10 करोड़ बाल मजदूरी या बंधुआ मजदूरी, 20 करोड़ युवा बेरोजगारी, 40 करोड़ शक्ति स्वरूपा मॉ-बहिनों को मर्द जाति की मानसिक गुलामी और अत्याचार झेलने, 80 करोड़ झूठ बोलने, ठगी, बेईमानी, अपराध करने, अत्याचार-अन्याय झेलने और तिल-तिल करके मरने को आभिशप्त हों ; ऐसे देश में बिना व्यवस्था परिवर्तन की बात किये, राष्ट्र-भक्ति, राष्ट्रभाषा, धर्म, चरित्र-सुधार, नैतिकता, आर्थिक विकास, योजनाओं और लोकतन्त्र की बातें करना या तो धूर्तता है या नैतिक अपराध या फिर वर्तमान संवैधानिक एंव आर्थिक अन्याय बनाये रखने का कुचक्र या राष्ट्रद्रोह।

कृपया विचार करें

हम अन्न, भोजन, कपड़ा, घर, मकान, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि बनाते या पैदा नहीं करते। 100 करोड़ देशवासी मिलकर पैदाकर, हमें, हमारे माता-पिता, बच्चों और आश्रितों को अन्न, भोजन, कपड़ा, घर, मकान, सड़कें, बिजली, यातायात और जीने की प्रत्येक सुख-सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

क्या हम उनके कर्ज और अहसानों को भूल जाएं? "उनसे हमें क्या मतलब" के भाव से उनके प्रति कृतज्ञता तक प्रदर्शित न करें? क्या हमें अपने "मैं" के अलावा 100 करोड़ के अहसान का कर्ज उतारने के बारे में विचारना नहीं चाहिए? क्या हम सब इतने अहसान फरामोश या नमक हराम हैं? या कि यह परिणाम है "फूट डालो और राज करो' वाली आज की उस व्यवस्था का ; जिसे आज की लुटेरी, अपराधी राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखना चाहती है?

सभी मानवीय व्यवस्थाएं अधूरी होती हैं, यह बात मानी जा सकती है, लेकिन उस व्यवस्था को सुधारने का कोई संकल्प कोई प्रयास नजर नहीं आए, तो यह एक खतरनाक स्थिति ह।

सभी धर्मों का सर्वसम्मत एवं सर्वमान्य मूल-प्राप्तव्य एवं मूल-कारण है : "कर्त्तव्य-उत्तरदायित्व निर्वाह"।